(ख) क्या यह सच है कि सीमांत और छोटे किसानों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे लाभ नहीं मिले हैं और बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण न दिये जाने के परिणामस्वरूप धनाभाव के कारण ग्रामीण शिल्पियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों के कार्यकरण में कुछ परिवर्तन लाने का है जिससे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स (घ). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में छटी योजना के दौरान देश के प्रत्येक ब्लाक में से सबसे गरीब 3000 परिवारों को सहायता देने की व्यवस्था है । सारे देश में लाभान्वित होने की संभावना वाले ऐसे परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ है । कार्यक्रम को समर्थन देने के वास्ते योजना में राजसहायता (सब्सिडी) इत्यादि के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है । राजसहायता की सीमा छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमांतिक किसानों और कृषि मजदूरों के लिए 33-1/3 प्रतिशत और जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत है । सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों के रूप में लाभ प्राप्त करने वालों को लगभग 3000/- करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने की सम्भावना है । वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यक्रम के अधीन ऋण संवितरण 200/- करोड़ रुपए के थे और लाभ प्राप्तकर्ताओं में छोटे/सीमांतिक किसान और ग्रामीण शिल्पकार शामिल थे । छठी योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम के अधीन लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं । योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, कार्यक्रम के अधीन की गई प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नए 20-सूत्री कार्यक्रम का भी एक भाग है । कमजोर वर्गों और 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्ताओं को त्वरित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लि बैंकों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं ।

Review Committee on working of Kshetriya Gramin Bank

*15. SHRI PRATAP BHANU SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to set up a review committee on the working of Kshetriya Gramin Banks; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) and (b). There is no proposal with the Government to set up any new Committee to review the working of Regional Rural Banks (Kshetriya Gramin Banks). A Steering Committee comprising representatives of Central Government, Reserve Bank of India, Public Sector Banks, National Federation of State Cooperative Banks, etc. is already functioning in the Reserve Bank under the Chairmanship of the Deputy Governor. The task of the Committee includes, *inter alia* supervision, monitoring and review of the working of Regional Rural Banks.

Offer from USSR to import textiles and export textile machinery and cotton to India

*17. SHRI MAGANBHAI BAROT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.S.S.R. has indicated its desire to

buy 2200 million metres of textile from the country and to offer inputs like textile machinery and cotton for the purpose;

(b) what is Government's reaction to this offer; and

(c) whether Government propose availing of this opportunity offered by the U.S.S.R. to bring the textile industry out of the crisis condition that it is facing these days and simultaneously institute steps to sustain improved production of textiles in the long run?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b). The USSR Government sounded the Governmtnt of India regarding the possibility of export of 500 million metres per annum of cotton fabrics from India on a long term basis. They also indicated the possibility of supply of textile machinery and raw cotton to India. The Government of India have reacted positively to the suggestion of increasing exports of cotton fabrics from India to the Soviet Union. Further details of the offer are awaited from USSR Government.

(c) The policy framework for the growth and development of the textile industry in India has been indicated in the Textile Policy announced by the Government of India on the 9th March, 1981.

Construction of aerodromes during current financial year

*18. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to lay a statement showing:

(a) the names of places where aerodromes have been sanctioned for construction during the current financial year in the country (State-wise);

(b) the names of such among them where construction has begun along-with the amount sanctioned dusing the current financial year in each case and the likely period of completion;

(c) the likely date by which the work on others would be taken in hand; and

(d) the names of such other places where the construction of aerodromes is under consideration, State-wise?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) Nil.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The proposal for construction of an aerodrome at Calicut in Kerala State is under consideration in the current financial year (1981-82).

देश में विदेशी मुद्रा की तस्करी धन्धा करने वाले व्यक्ति

*19. **श्री अशोक गहलोत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की तस्करी करने वालों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस प्रकार की गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी मुद्रा के